सत्ता की फिक्र में पर्यावरण ताक पर

पुण्य प्रसून वाजपेयी

सत्ता होगी तो ही काम करेगे। सत्ता जा रही होगी तो फिर सत्ता बचाने के लिये काम करेगें। और सत्ता जब नहीं होगी तो जो सत्ता में है वह समझे यानी जिम्मेदारी ले। मानिये या ना मानिये देश कुछ इसी मिजाज से चलता है। और इसका ताजा उदाहरण है पर्यावरण या कहे प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार की समझ। संयोग ऐसा हुआ कि जिस दिन गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बडी प्रतिमा का अनावरण प्रधनमंत्री को स्टेच्यू आफ यूनिटी के नाम से करना था। उसी दिन जेनेवा में ग्लोबल एयर पोल्यूशन बैठक थी। और अगला संयोग यही था कि इसी दौर में दिल्ली गैस चैंबर में बदल रही थी और है भी। और उससे भी बडा संयोग ये था कि मोदी सरकार और सत्ताधारी बीजेपी ने देश भर में इसी दिन यूनीटी रन रखा यानी एकता दौड़। तो हुआ क्या ?

एक तरफ जब पूरी दुनिया हवा में बढते प्रदूषण से परेशान है तो दुनिया के कमोवेश देश के प्रतिनिधि जेनेवा पहुंचे। वहा विश्व स्वास्थ्य संगठन में बैठक में शिरकत की। अपनी अपने विचार रखे। तो दूसरी तरफ भारत का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने जेनेवा में पहुंच नहीं पाया। क्योकि सभी देश में 'यूनिटी रन' को सफल बनाने में लगे थे। चूकि डब्ल्यूएचओ पहली बार वायु प्रदूषण को लेकर इस तरह का सम्मेलन कर रहा था। और दुनिया भर की रिपोर्ट में जब ये आया कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत के हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीन केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को निमंत्रण भेजा।

खासकर भारत की मुश्किलो को लेकर भारत के प्रतिनिधि क्या कहते हैं इस पर डब्ल्यूएच ओ ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशो की नजर थी। क्योकि विकासशील देश भारत बिजनेस के लिये एक बाजार के तौर पर उभर रहा है और आईएमएफ तथा विश्व बैक भी चाहते है कि भारत पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र

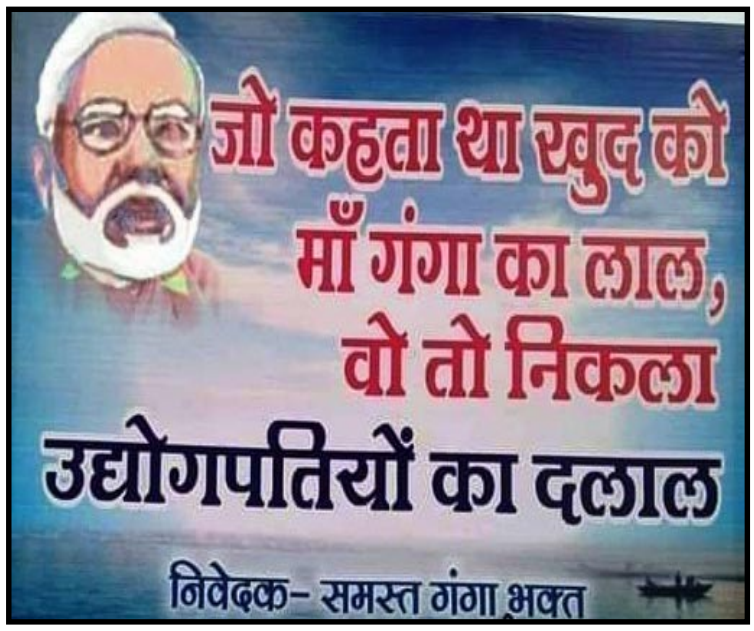

और पेरिस समझौतों में जो चिंता जता रहा है वह पहली बार वायु प्रदूषण को लेकर होने वाले सम्मेलन में भी उभरे। लेकिन सरदार के लिये सत्ता की एकता दौड़ यानी 'यूनिटी रन' ही इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि कोई भी सम्मेलन में शामिल होने गया ही नहीं। यानी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये ग्लोबल एयर पाल्युशन के सम्मेलन में भारत का कोई नहीं पहुंचा।

देश के पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली में रन फार यूनिटी में व्यस्त हो गये। तो स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा गुवाहटी में यूनिटी रन कराने लगे तो मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेशवर में यूनिटी रन को झंडा दिखाने पहुंच गये। यानी एक तरफ प्रदूषण से लेकर भारत का हाल कितना बुरा है ये इससे भी समझा जा सकता है कि 2016 में पांच बरस से कम के एक लाख बच्चों की मौत प्रदूषण की वजह से हो गई। और आंकडे बताते हैं कि हर मिनट 5 लोगों की मौत देश में सिर्फ प्रदूषण से हो जाती है । यानी साल भर में 25 लाख से ज्यादा लोग देश में प्रदूषण से मर जाते है। और इससे निजात कैसे मिले, इसपर जब दुनियाभर के विशेषज्ञ और स्कालर वायु प्रदूषण पर चर्चा कर रहे थे । खास कर पहली बार वायु प्रदूषण के मद्देनजर प्रकृति के मल्टी-डायमेशनल दोहन की वजह से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा हो रही थी।

उसके बाद दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि इसलिये जुटे कि जो भी रिजल्ट निकले उसमें वह अपने अपने देश लौटने के बाद उन कदमों को उठाये जिसे जेनेवा में पास किया गया। पर भारत की तरफ से आखिरी दिन दो नौकरशाहों की मौजूदगी रही जो कहते क्या या सुनते क्या ये भी हर कोई जानता है । क्योकि देश तो चुनावी मोड में चला गया है तो सत्ता को फिक्र सत्ता बरकरार रखने की ज्यादा है। तो सारे काम चुनावी जीत के मद्देनदर ही हो रहे हैं। और सच भी यही है कि पीएमओ से लेकर नीति आयोग तक में बैठे नौकरशाह सिर्फ रुटिन कार्य कर रहे है। और कई मंत्रालयों में तो सारे काम ठप पडे हैं । या कहे सारे सत्ता की चुनावी जीत बरकरार रखने में सिमट चुके हैं। खास बात तो ये भी है कि पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं बल्कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिये भी भारत ने जितने कार्यक्रम बनाये हैं और दुनिया के तमाम देशों को जो सुझाव अपने प्रोग्राम के नाम के जरिये भारत देता है वह शानदार है। लेकिन भारत में ही कोई प्रोग्राम पूरा नहीं होता ।

मसलन, देश के सौ शहरों के लिये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को निर्धारित वक्त में पूरा करना था। लेकिन ये पूरा तो दूर कई शहरों में शुरु ही नहीं हो पाया । यानी जैसे सत्ता को लगता है वह अनंतकाल तक रहे । वैसे ही हर पालिसी भी अनंतकाल तक चलती रही। सोच यही है । और असर इसी का है कि प्रदूषण के बोल बड़े-बड़े है लेकिन उस लागू कोई करता नहीं तो फिर हालात ये भी है कि देश में पर्यावरण मंत्रालय का कुल बजट ही 2675 करोड 42 लाख रुपये है।

यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में खर्च हो गये 3870 करोड़। औसतन हर बरस बैंक से उधारी लेकर ना चुकाने वाले रईस 10 लाख करोड़ डकार रहे हैं। राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में ही तीन लाख करोड़ से ज्यादा प्रचार प्रसार में फूंकने की तैयारी हो चुकी है । लेकिन देश के पर्यावरण के लिये सरकार का बजट है 2675.42 करोड़ । और उस पर भी मुश्किल ये है कि पर्यावरण मंत्रालय का बजट सिर्फ पर्यावरण संभालने भर के लिये नहीं है । बल्कि दफ्तरों को संभालने में 439.56 करोड़ खर्च होते हैं। राज्यों को देने में 962.01 करोड खर्च होते हैं। तमाम प्रोजेक्ट के लिये 915.21 करोड़ का बजट है। तो नियामक संस्थाओं के लिये 358.64 करोड का बजट है। यानी इस पूरे बजट में से अगर सिर्फ पर्यावरण संभालने के बजट पर आप गौर करेंगें तो जानकार हैरत होगी कि सिर्फ 489.53 करोड़ ही सीधे प्रदूषण मुक्ति से जुड़ा है जिससे दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत हर बरस परेशान हो जाता है।

और प्रदूषण को लेकर जब हर कोई सेन्ट्रल पौल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से सवाल करता है तो सीपीसी का कुल बजट ही 74 करोड 30 लाख का है । तो पर्यावरण को लेकर जब देश के पर्यावरण मंत्रालय के कुल बजट का हाल ये है कि देश में प्रति व्यक्ति 21 रुपये सरकार खर्च करती है । और इसके बाद इस सच को समझिये कि एक तरफ देश में पर्यावरण मंत्रालय का बजट 2675.42 करोड है । दूसरी तरफ पर्यावरण से बचने का उपाय करने वाली इंडस्ट्री का मुनाफा 3 हजार करोड से ज्यादा का है । तो पर्यावरण को लेकर इन हालातों के बीच ये सवाल कितना मायने रखता है कि देश के पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन पिछले बरस जब दिल्ली गैस चैबर बनी तब जर्मनी में थे और इस बार जब गैस चैबर से मुक्ति के उपाय के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेनेवा आने को कहा तो इंडिगा गेट पर "रन फार यूनिटी" के लिये झंडा दिखाकर दौड रहे थे ।

ऐसे में आखरी सवाल जीने के अधिकार का भी है क्योकि संविधान की धारा 21 में साफ साफ लिखा है जीने का अधिकार ।

और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने के अधिकार को पहली बार उस समय मान्यता दी गई थी, जब रूरल लिटिगेसन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम राज्य, AIR 1988 SC 2187 (देहरादून खदान केस के रूप में प्रसिद्ध) केस सामने आया था। यह भारत में अपनी तरह का पहला मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण व पर्यावरण संतुलन संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में गैरकानूनी खनन रोकने के निर्देश दिए थे।

वहीं एमसी मेहता बनाम भारतीय संघ, AIR 1987 SC 1086 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुछेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के मौलिक अधिकार के अंग के रूप में माना था। तो फिर दिल्ली के वातावरण में जब ज़हर धुल रहा है, देश में हर मिनट 5 लोगों की मौत पप्रदूषण से हो रही है, तो क्या सत्ता सरकार इस चिंता से वाकई दूर है। या फिर सत्ता गंवाने की चिंता ने कहीं ज्यादा जहर फैला दिया है ।

लखनऊ में लाठी खाते नौजवान और लोकतंत्र के कुछ सवाल

प्रेगनेंसी में नारियल जरूर खाएं ? आखिर क्या है रोगों के संबंध में नक्षत्रों की भूमिका ? येल यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में कैसे पहुंची बिहार से सूर्य की कलाकृति ?

लखनऊ से कई नौजवान की लाठी से घायल अपने साथियों की तस्वीरें भेज रहे हैं। यह ख़बर कई जगह छपी है। किस रूप में छपी है यह तो लाठी खाने वाले नौजवान ही बता सकते हैं। लोकतंत्र में अपने प्रति और दूसरों के प्रति लापरवाह होने का यह सब नतीजा है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके भीतर लाठी खाने वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी और जो लाठी खा रहे हैं उनके भीतर भी किसी दूसरे समूह के लाठी खाने पर सहानुभूति नहीं होगी। यह स्थिति नागरिकों को बेबस करती है। नागरिक खुद को भी बेबस करते हैं।

मामला 68,500 शिक्षक भर्ती का है जिसके लिए 9 जनबरी 2018 को शासनादेश आया कि परीक्षा पास करने के लिये सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 45 न एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 40 प्रतिशत ज़रूरी होंगे। 12 मार्च को परीक्षा होनी था मगर कोर्ट से स्टे हो गया। यूपी टेट में लगभग 5000 पास हुये अभ्यथियों को परीक्षा में शामिल करने के लिये परीक्षा की नयी तिथि 27 मई 2018 रखी। इसी बीच योगी जी ने 21 मई 2018 को शिक्षक भर्ती परीक्षा की पासिंग मार्क में संशोधन कर दिया और सामान्य जाति और पिछड़ा बर्ग के लिये 33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये 30 प्रतिशत अंको को निर्धारित कर दिया गया। 27 मई को परीक्षा सम्पन्न हो गयी और परीक्षा की उत्तर माला भी आ गयी। दिवाकर सिंह ने मान्यनीय इरशाद अली जी की लखनऊ खंडपीठ में 21 मई के संशोधित शासनादेश 30 प्रतिशत/ 33प्रतिशत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और दिवाकर सिंह को 30प्रतिशत/33प्रतिशत पर कोर्ट द्वारा स्टे लगा दी गयी। सरकार से तीन सप्ताह के भीतर उसका पक्ष माँगा गया लेकिन सरकार ने परिणाम घोषित कर दिए। परिणाम घोषित हुए पहले आदेश के हिसाब से जब कटऑफ़ चालीस फ़ीसदी से अधिक था। इसमें कुल 41556 अभ्यर्थी पास हुये।

लखनऊ में जिन छात्रों पर लाठियाँ बरसीं हैं वे कट ऑफ़ को योगी सरकार के दूसरे आदेश के हिसाब से करने की माँग कर रहे हैं। यानी तीस प्रतिशत वाला कट ऑफ़। इनका कहना है कि 68,500 में से 27,000 पद ख़ाली हैं। अगर कट ऑफ़ नीचे होगा तो इन लोगों की नौकरी हो जाएगी। अगर इसके लिए दोबारा इम्तिहान होंगे तो उम्र सीमा पार हो जाएगी और इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। 12 नवंबर को 30/33 कट ऑफ़ वाले मामले की सुनवाई है और अगर सरकार इसके पक्ष में दलील दे तो इनका जीवन बच सकता है। नौकरी मिल सकती है। अगर 40/45 प्रतिशत कट ऑफ से मेधावी खोजने का ही तर्क है तो फिर कट ऑफ 80 फीसदी होना चाहिए था। 30 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के कट ऑफ के अंतर पर कोई महान विद्वान नहीं मिल जाते हैं। इस पर बात हो सकती है कि भर्ती की यह प्रक्रिया सही है या नहीं। तो यह 30 प्रतिशत पर भी बेकार है और 40 प्रतिशत पर भी।

सभी राज्यों में नौकरियों को लेकर जानबूझकर कर प्रक्रियाएँ जटिल की जाती हैं ताकि कोर्ट में मामला चलता रहे। नौजवान भी अपने हिस्से का संघर्ष कर ही रहे हैं लेकिन इन भर्तियों की राजनीति को समझने के लिए अलग तरह की विद्वता चाहिए। अलग तरह की जानकारियाँ ताकि इन्हें समग्रता में देखा जा सके। फ़ौरी तौर पर इनकी राजनीति बताती है कि भारत के युवा राजनीतिक रूप से महत्वहीन हो चुके हैं। मैं प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज़ के दौरान कहता था कि युवाओं की राजनीतिक समझ थर्ड क्लास है तभी नेता इन्हें नचा ले जाते हैं। तब लगता था कि मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा लेकिन मैं अपनी बात पर फ़िलहाल टिके रहना चाहूँगा। लखनऊ ने ही अलग अलग भर्तियों के कई प्रदर्शन देखे, लाठी चार्ज देखे, मगर खुद युवा इन्हें समग्र रूप में नहीं देख पाए। कोई रणनीतिक और राजनीतिक समझ नहीं बना पाए। लाखों छात्र परेशान हैं, मगर कभी एक साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण परीक्षा प्रणाली के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी ताकत को छांट कर, बांट कर लड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं।

लग रहा है कि हम लोकतंत्र के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहाँ लोक यानी जनता सिर्फ पीड़ित है। लाभार्थी नहीं है। जो अमीर हैं। उद्योगपति हैं वही लाभार्थी हैं। यह बदलाव सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने से नहीं आता बल्कि घंटों पढ़ने, संघर्ष करने और समझने से आता है। इसके लिए चंद लोग तो लगे रहते हैं, उनकी छोटी कामयाबी से रौशनी भी दिखती है मगर अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जला देने से रौशनी तो आती है, अंधेरा दूर नहीं होता। उस रौशनी में कमरे में पड़ी हर चीज़ साफ़ साफ़ नहीं दिखती है।

- साइबर नजर

अकबर ने दीपावली में पटाखे छोड़ने का रिवाज प्रारंभ किया

औरंगज़ेब तक ने उस परम्परा को निभाया. दीपावली के बारे में ब्राह्मणों ने भ्रम फैला रखा है. इससे रामायण जैसे मिथक का कुछ लेना देना नही है. अयोध्या कोई देश नहीं था, बल्कि कोशल महाजनपद का एक टाउन था. चक्रवर्ती बनने के लिए राजा राम ने शेष किन किन राज्यों पर विजय प्राप्त की, आज तक इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता.

अगर देश की सीमा के लिहाज़ से देखें तो जिस समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया उसने अंग, मगध के राजाओं सहित कोशल महाजनपद के सम्राट को भी आमंत्रित किया था. मतलब कोशल एक राज्य था और अयोध्या उसका अंग तो राजा दशरथ कोई सामंत टाइप ही रहे होंगे. ऐसे भी किसी छोटे से इलाके के सामंत में इतनी ताकत नहीं होती कि पूरे देश में अपना विजयोत्सव मनवा ले. अत: यह मानने का कोई ऐतिहासिक कारण नहीं है कि राजा राम के अयोध्या लौटने पर पूरे देश में दीपावली मनाई गई थी. अगर ऐसा होता तो खुद ब्राह्मण अपने धार्मिक ग्रंथों में दीपावली का वर्णन करते. अंग्रेजों से लेकर मुसलमान शासकों तक ने इसका वर्णन किया होता. हाँ, दीपावली सदियों से मनाई जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं.

सवाल यह है कि लोकोत्सव को इन मिथकों से कब जोड़ा गया और क्यों ? यही वह सवाल है, जिसका उत्तर जानने की जरूरत है.

अब तो हद ही गई है. इन मिथकों को मेटरलाइज किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है. कांग्रेस ने तथाकथित ब्राह्मणवादी इतिहासकारों की मदद से भारत के असली इतिहास की कब्र खोदा, बीजेपी उस पर मिट्टी डाल रही है. मिथक इतिहास बन रहे हैं. बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ी अगर मिथक को इतिहास समझने लगे तो समझ लीजिए गुलामी की आयु सनातन हो जायेगी. ब्राह्मणवाद रूपी सामंतवाद रोज प्रपंच गढ़ रहा है. इसके विरुद्ध सारे बुद्धिजीवियों को एकजुट होना पड़ेगा.

कमाल की बात है कि इस प्रपंच को गढ़ने में मुगल वंश का बड़ा हाथ रहा है. ब्राह्मणों के संरक्षण में सरकारी होली, सरकारी दीवाली इन्होंने ही शुरू किया. इसे सरकारी आयोजन स्थापित किया. लोक के ऊपर ब्राह्मण की सर्वोच्च सत्ता स्थापित की. यह कोई संयोग नहीं कि अवधी, भोजपुरी में रामचरितमानस अकबर के सहयोग और अकबर काल में लिखा गया. क्योंकि निर्गुण राम के भक्ति आंदोलन से मुगलिया सल्तनत डर गया था, इसलिए उसने सामंत राम को स्थापित करने के लिए लोकभाषा में रामचरित मानस लिखवाया. लोक के निर्गुण राम को सामंत राजा राम में सबमर्ज किया गया. कालांतर में उसको अक्षुण बनाए रखने के लिए उपाय गढ़े गए... रामलीला मंडली तैयार की गई... सरकारी छुट्टी तय की गई... गांव-गांव में रामलीला दिखाया गया. टेक्नॉलाजी जब उनके हाथ लगी तो रामायण सीरियल बनाकर पूरे देश को भक्त बनाया गया. उनमें उन्माद फैलाया गया. बाद में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया. उल्लेखनीय है कि जिस बाबर के खानदानों ने ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, ब्राह्मणवादी ज्यादा उन्हीं को गाली देते हैं.

लेकिन इस देश की नस में ब्राह्मणवाद विरोधी रक्त सदियों से प्रवाहमान रहा है. भले ही कुछ समय के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया गया हो, लेकिन रामायण और रामलीला कल भी आम जनता के लिए आस्था नहीं बल्कि मनोरंजन का विषय था, आज भी है. उसका मंचन करनेवाले लोगों को कल भी जनता कलाकार , भांड समझती थी, आज भी समझती है. इसी तरह दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाना आस्था का विषय नहीं बल्कि उत्सव में मनोरंजन का विषय है. यह देश का हर नागरिक जानता है.

- मनीष चांद